



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 2019/वैशाख 12 1941

No. 136] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2019/VAISAKHA 12, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2019

अंतिम जांच परिणाम

विषय – दिनांक 18.01.2018 को शुरू की गई जूट यार्न की जांच के संबंध में मैसर्स नेचुरल जूट मिल (उत्पादक/निर्यातक), बांग्लादेश और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल एलएलसी (निर्यातक/व्यापारी), संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार बांग्लादेश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित जूट उत्पादों यथा-जूट यार्न/ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/केबिल्ड एवं सिंगल), हेसियन फैब्रिक और जूट यार्न के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के तहत न्यू शिपर समीक्षा।

फा. सं. 7/09/2017-डी जी ए डी.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

क. मामले की पृष्ठभूमि:

2. जबकि मूल पाटनरोधी जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने 20 अक्टूबर, 2016 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना 14/19/2015-डीजीएडी द्वारा सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 69 के तहत आने वाले, बांग्लादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित जूट उत्पादों यथा-जूट यार्न/ट्वाइन

(मल्टीपल फोल्डेड/केबिल्ड एवं सिंगल), हेसियन फैब्रिक और जूट सेकिंग बैगों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की। केंद्र सरकार ने 05 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)-सीमा शुल्क और 03 अप्रैल, 2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 11/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा निश्चात्मक पाटनरोधी शुल्क अधिसूचित किया।

3. मैसर्स नेचुरल जूट मिल (उत्पादक/निर्यातक), बांग्लादेश और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल एलएलसी (निर्यातक/व्यापारी), संयुक्त राज्य अमेरिका ने बांग्लादेश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित जूट यार्न, जो मूल जांच की जांचावधि के दौरान उनके द्वारा निर्यात नहीं किए गए थे जिसमें 03 अप्रैल, 2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 11/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा पाटनरोधी उपाय लगाए गए हैं, के आयातों के संबंध में अलग-अलग पाटन मार्जिन का दावा करते हुए न्यू शिपर समीक्षा (एनएसआर) का अनुरोध करते हुए सीमा प्रशुल्क अधिनियम के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार न्यू शिपर समीक्षा (एनएसआर) के लिए आवेदन दायर किया।
4. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के तहत उल्लिखित शर्तों से प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट होने पर मैसर्स नेचुरल जूट मिल (उत्पादक/निर्यातक), बांग्लादेश और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल एलएलसी (निर्यातक/व्यापारी), संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में बांग्लादेश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित जूट यार्न (संबद्ध सामान) के पाठित आयातों पर लगाए गए शुल्क के निर्धारण के लिए 18 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 7/9/2017-डीजीएडी द्वारा न्यू शिपर समीक्षा जांच शुरू की।
5. वित्त मंत्रालय ने 23 मार्च, 2018 की अधिसूचना संख्या 16/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा उपर्युक्त एनएसआर जांच के पूरा होने पर संबद्ध सामानों के लिए मैसर्स नेचुरल जूट मिल (उत्पादक/निर्यातक), बांग्लादेश और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल एलएलसी (निर्यातक/व्यापारी), संयुक्त राज्य अमेरिका लिमिटेड द्वारा किए गए निर्यातों का अनंतिम मूल्यांकन अधिसूचित किया।
6. इस न्यू शिपर समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 तक निर्धारित की गई थी।

ख. प्रक्रिया

7. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - (i) प्राधिकारी ने संबद्ध एनएसआर पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित 18 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 7/9/2017-डीजीएडी द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
 - (ii) प्राधिकारी ने निर्यातक प्रश्नावली की प्रति सहित आवेदक को जांच की शुरूआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उन्हें लिखित में अपने ज्ञात विचार देने तथा जांच की अवधि की समाप्ति के बाद निर्धारित प्रश्नावली में संगत आंकड़े दायर करने का अवसर प्रदान किया।
 - (iii) प्राधिकारी ने भारत में बांग्लादेश उच्च आयोग को भी जांच की शुरूआत की अधिसूचना की प्रति भेजी।
 - (iv) प्राधिकारी ने भारत में ज्ञात घेरेलू उत्पादकों को जांच की शुरूआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उन्हें लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अवसर प्रदान किया।
 - (v) जांच की शुरूआत की अधिसूचना के उत्तर में प्रश्नावली का उत्तर एनएसआर के लिए आवेदक मैसर्स नेचुरल जूट मिल (उत्पादक/निर्यातक), बांग्लादेश और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल एलएलसी (निर्यातक/व्यापारी), संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दायर किया गया था।
 - (vi) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अनुरोधों/ सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
 - (vii) प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार, मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने और उसके बाद लिखित अनुरोध करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने हेतु 14 फरवरी, 2019 को मौखिक सुनवाई की। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विचारों/सूचना के संबंध में खंडन प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों पर उपर्युक्त रूप से विचार किया है।

- (viii) प्राधिकारी ने प्रतिभागी हितबद्ध पक्षकारों को 22 अप्रैल, 2019 को प्रकटन विवरण जारी किया।
- (ix) जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी संगत अनुरोधों/टिप्पणियों पर विचार किया गया है और इस प्रकटन विवरण में शामिल किया गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद

8 मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद "जूट उत्पाद" है जिसमें जूट यार्न/ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/केबिल्ड एवं सिंगल), हेसियन फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग हैं। प्राधिकारी ने मूल जांच में जूट उत्पादों के प्रत्येक किस्म के लिए उत्पादकों को अलग-अलग शुल्क की सिफारिश की थी। यह जांच केवल जूट यार्न अर्थात् 18.01.2018 की जांच की शुरूआत की अधिसूचना के पैरा 1 में उल्लिखित मूल जांच में विचार किए गए विचाराधीन उत्पाद की एक उत्पाद किस्म के निर्यातों के संबंध में है।

घ. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

9. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध:

- i. जांच 18 जनवरी, 2018 को शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने 25 अप्रैल, 2018 को मामले की शुरूआत करने के पूर्व ही एनएसआर जांच के लिए नई प्रश्नावली का प्रपत्र बनाया था। यह याचिका व्यापार सूचना जारी करने से पूर्व दायर की गई हो सकती है। फिर भी आवेदक का जांच की शुरूआत के बाद व्यापार सूचना के अनुसार अद्यतन सूचना दायर करने का दायित्व था। पर्याप्त समय और जानकारी होने के बावजूद आवेदक ने नए आवेदन प्रपत्र के अनुसार सूचना संशोधित नहीं की।
- ii. यद्यपि अधिकृत न्यू शिपर को अलग मार्जिन की मांग करने का अधिकार है, परंतु साथ ही निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि दावे अधिकृत हैं और पाटनरोधी शुल्क के संबंध में कोई गलत/दुष्प्रयोग/प्रवंचना नहीं है। यह इस कारण है कि आवेदक को यह पूर्णतः सिद्ध करने की आवश्यकता होती है कि (क) वे उपयुक्त/अधिकृत निर्यातक हैं जिन्होंने अधिकृत विक्री की है, (ख) उन्होंने मूल जांच में सामानों का निर्यात नहीं किया है और (ग) वे संबद्ध सामानों के उत्पादक/निर्यातक से संबंधित नहीं हैं जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगना है। निर्यातकों ने इन मानदंडों को पूरा नहीं किया है।
- iii. निर्यातक/उत्पादक को यह दर्शाना चाहिए कि उन्होंने मूल जांच की जांचावधि के दौरान संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है और वे उन उत्पादकों से संबंधित नहीं हैं जिन्होंने मूल जांचावधि में सामानों का निर्यात किया है। आवेदन पत्र में और बाद के अनुरोधों में ऐसा कुछ नहीं है जो यह दर्शाएँ कि यह आवश्यकता साध्यों के समर्थन के साथ पूरी की गई है।
- iv. आवेदक ने जांच की अवधि के रूप में वर्तमान अवधि अर्थात् उस अवधि की मांग की है जो कि नियम 22 के तहत जांच की शुरूआत के बाद की अवधि है। संभावित समीक्षा अवधि की संकल्पना की टाइल्स मामले में सेसटेट द्वारा भारी आलोचना की गई है।
- v. जांच की संभावित अवधि के कारण आवेदक (क) केवल समारोह निर्यात अर्थात् 45 मीट्रिक टन निर्यात करके, (ख) अत्यधिक कृत्रिम रूप से उच्च कीमत पर करके कीमत में छेड़द्वाड़ करने/बनाने में सक्षम रहे हैं। यहां यह नोट करना व्यावहारिक है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद बांग्लादेश से आयात जांच की अवधि के दौरान 45,000 मी. टन थे जिसकी तुलना में आवेदक द्वारा किए गए निर्यात केवल 45 मी. टन हैं जो कि निर्यातों का 0.1 प्रतिशत है।
- vi. मौखिक सुनवाई के दौरान आवेदक ने तर्क दिया था कि कम निर्यात इसलिए थे क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा अनंतिम मूल्यांकन अधिसूचना 23 मार्च, 2018 को आई। जांच की शुरूआत के दो माह के भीतर केंद्र सरकार ने सामानों के अनंतिम मूल्यांकन के लिए अधिसूचना जारी की। आवेदक के पास फिर भी सामानों का निर्यात करने के लिए 09 माह थे परंतु उसने फिर भी केवल 45 मी. टन सामानों का निर्यात करने का विकल्प चुना।
- vii. जांच शुरू होने पर आवेदक अपने सामानों के निर्यात के लिए संभावित ग्राहकों के साथ आसानी से संविदा कर सकता था। इस प्रकार, आवेदक अधिसूचना जारी किए जाने के बाद उसके पास समयावधि का सही प्रयोग उसने नहीं किया। जैसा कि इस 09 माह की अवधि के दौरान उसके द्वारा किए गए निर्यातों से देखा

जा सकता है। उसने पूरी जांच की अवधि में केवल दो निर्यात किए हैं जो यह दर्शाता है कि वे वर्तमान जांच के संबंध में गंभीर नहीं हैं।

- viii. आवेदक के व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि वे वर्तमान मामले की स्थिति के संबंध में गंभीर नहीं हैं और वर्तमान अभ्यास उनका भाग्य आजमाने का है, यदि वे अनुकूल मार्जिन प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि इस तथ्य से देखा जा सकता है कि उन्होंने आवेदन पत्र दायर करने के बाद और संभावित जांच की अवधि लेने पर केवल दो बार निर्यात किया है। आवेदक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने उत्पाद के लिए व्यापारी भी सुरक्षित किया है न कि भारत और चीन में जहां उसने निर्यात किए हैं।
- ix. प्राधिकारी ने विगत में की गई बिक्री के बारे में संतुष्ट होने पर और निर्यातों के लिए की गई दृढ़ प्रतिबद्धता पर ही न्यू शिपर समीक्षा जांचें शुरू की हैं। न्यू शिपर समीक्षा मामले में जांच की अवधि के दौरान आवेदक द्वारा किए गए निर्यात पाटन मार्जिन के लिए आधार होने हेतु अधिकृत वाणिज्यिक लेन-देन होना चाहिए। यह देखे जाने की आवश्यकता है कि क्या विचाराधीन बिक्री विशिष्ट है और न्यू शिपर की भावी बिक्री की प्रतिनिधि कारक होगी। यदि किसी उत्पादक अथवा निर्यातक के लेन-देन में कीमत, मात्रा और समग्र परिस्थितियां शामिल हैं जिन पर प्रश्न उठाया जा सकता है तो उन बिक्रियों की वाणिज्यिक वैधता, उन बिक्रियों की उपयुक्ता, मूल्य और मात्रा के संबंध में दोनों की जांच की जानी चाहिए।
- x. संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, यूरोपीय संघ, टर्की, ताइवान और वियतनाम आदि जैसे दूसरे देशों के कानूनों को नोट करना इस संबंध में व्यावहारिक है जिनमें भी यह प्रावधान है कि निर्यातक द्वारा किए गए लेन-देन अधिकृत और प्रकृति में वाणिज्यिक होने चाहिए।
- xi. प्राधिकारी ने विशेष रूप से निर्धारित किया है कि निर्यातक द्वारा निर्यातित मात्रा वाणिज्यिक मात्रा में होनी चाहिए ताकि अलग पाटन मार्जिन प्राप्त कर सके। आवेदक ने तर्क दिया था कि व्यापार सूचना हाल ही में जारी की गई है और इस प्रकार भावी मामलों के लिए उसका प्रभाव होना यह अनुरोध है कि उल्लिखित सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं है। वाणिज्यिक मात्रा में किए जा रहे वास्तविक निर्यात के सिद्धांत को विगत में प्राधिकारी तथा माननीय सेसटेट ने माना है। इस प्रकार, यह सिद्धांत वर्तमान मामले में अत्यधिक लागू है। एच एंड आर जॉनशन (इंडिया) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा जनता जूट मूल द्वारा पीसीवी फ्लेक्स फिल्म, आर-134ए, जूट उत्पादों में प्राधिकारी के विगत निर्णय का संर्द्ध दिया जाता है।
- xii. विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं है। इससे भी तथ्य द्विपाने के सजग प्रयास की गंध आती है कि कम अथवा नगण्य पाटन मार्जिन प्राप्त करने के लिए और उसके बाद मात्राओं का आक्रामक रूप से पाटन करने के लिए अवास्तविक कीमत पर टोकन निर्यात किया गया था।
- xiii. आवेदकों ने विना किसी कारण के और घरेलू उद्योग से सूचना द्विपाने के पूर्ण उद्देश्य से तथा घरेलू उद्योग को उसके हितों की रक्षा करने से रोकने के लिए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- xiv. उपर्युक्त अनुरोध के पूर्वाग्रह के बिना कि आवेदक ने अलग पाटन मार्जिन प्रदान करने के लिए अपने मामले को सिद्ध नहीं किया है, यदि प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आवेदक शर्त पूरी करते हैं तथा अलग शुल्क औचित्यपूर्ण हैं तो फिर यह अनुरोध है कि आवेदक को मूल जांच में नमूने में शामिल न की गई सहयोगी कंपनियों को दिया गया भारित औसत शुल्क दिया जाए क्योंकि मूल जांच में नमूनाकरण शामिल है।
- xv. घरेलू उद्योग ने जहां तक आवेदन के तर्क का संबंध है, प्रत्युत्तर में यह अनुरोध है कि "वाणिज्यिक मात्राओं" शब्द का प्रयोग भारतीय नियमावली और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुरूप नहीं है, घरेलू उद्योग अपना रूप दोहराना चाहेगा कि वाणिज्यिक मात्रा शब्द डब्ल्यूटीओ और भारतीय पाटनरोधी शुल्क नियमावली के विपरीत नहीं है, न्यू शिपर समीक्षा की मांग करने वाले निर्यातकों की आवश्यकता विभिन्न डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के कानूनों में ही विद्यमान नहीं है, इस आवश्यकता पर भारतीय न्याय व्यवस्था सबसे अधिक नोट करने योग्य एचआर जॉनसन मामले में भी चर्चा की गई है।

- xvi. यदि किसी निर्यातिक को निर्यातों की छोटी सी मात्रा के आधार पर अथवा निर्यातों की उम्मीद के आधार पर पाटन मार्जिन दिया जाता है तो यह निर्यातिक द्वारा कम मार्जिन प्राप्त करने हेतु कीमतों में छेड़छाड़ करने की खुली गुंजाइश होगी। यह इस कारण भी है कि न्यू शिपर समीक्षा की मांग करने वाले निर्यातिकों के लिए पात्रता मानदंड के रूप में काफी निर्यात करने की प्रतिबद्धता अथवा वाणिज्यिक निर्यात लेन-देन अथवा पर्याप्त निर्यात की स्थिति अधिकतर न्यायिक क्षेत्रों ने शुरू की है।
- xvii. प्रत्येक डब्ल्यूटीओ करार देश में पाटनरोधी कानून तथा प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 तथा अनुच्छेद VI अर्थात् मूल करार के कार्यान्वयन संबंधी करार पर आधारित है। इस प्रकार, इन देशों में कानून मूल करार के अनुरूप हैं और इन देशों द्वारा तैयार किए गए सभी कानूनी प्रावधान तथा अपनाई गई परिपाटी डब्ल्यूटीओ जांच के अध्यधीन हैं। इस प्रकार, अन्य देशों की परिपाटी शामिल सिद्धांतों और सिद्धांत प्रक्रियाओं जिनका पालन पाटनरोधी जांच में किया जा सकता है, में उचित मार्गदर्शन का प्रावधान है।

10. आवेदक निर्यातिक द्वारा किए गए अनुरोधः

- यह अनुरोध है कि जब भी प्राधिकारी ने कोई सूचना मांगी है तो उन्होंने सभी सूचनाएं दी हैं। याचिकाकर्ता नियम 22 की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और प्राधिकारी द्वारा उसकी पहले ही जांच कर ली गई है और तब ही वर्तमान जांच शुरू की गई थी। आईजेएमए के दावे आधारहीन और अस्पष्ट हैं।
- आवेदक एतद्वारा अनुरोध करते हैं कि उन्होंने पाटित आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए नियम 22 के अनुसार 22 मई, 2017 को प्राधिकारी के पास एनएसआर जांच की शुरूआत के लिए आवेदन दायर किया है। उसके बाद, प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2017 को एक कमी वाला पत्र जारी किया गया था। आवेदकों ने दिनांक 28 अगस्त, 2017 के पत्र द्वारा सभी सूचनाएं दी हैं। आवेदकों ने माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी दिनांक 07 दिसंबर, 2017 के पत्र संख्या 7/9/2017-डीजीएडी के उत्तर में 26 दिसंबर, 2018 के पत्र द्वारा पूरक सूचना भी दायर की है। फिर प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा दी गई सभी सूचनाओं की जांच करने के बाद 18 जनवरी, 2018 को वर्तमान जांच शुरू की। याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 11 फरवरी, 2019 के पत्र द्वारा प्राधिकारी के पास नए प्रपत्र के अनुसार अपेक्षित प्रश्नावली के उत्तर भी दायर किए हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के पास उपलब्ध पूरी सूचना प्राधिकारी को दी गई है।
- यह भी अनुरोध किया जाता है कि यह जांच शुरू करने के लिए आईजेएमए प्राधिकारी की बुद्धिमत्ता पर अंगुली उठा रहे हैं। इस पहलू की जांच प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच शुरू करने से पूर्व विस्तार से की गई है और ऐसे आधारहीन मुद्दों को उठाने का यह सही समय नहीं है।
- जिस व्यापार सूचना की बात आईजेएमए कर रहा है वह 25 अप्रैल, 2018 को यह उल्लिखित करते हुए जारी की गई थी कि:

"4. सभी हितबद्ध पक्षकारों से इस सूचना के जारी होने की तारीख के बाद न्यू शिपर समीक्षा की शुरूआत के लिए कोई नया अनुरोध दायर करने हेतु संलग्न आवेदन प्रपत्र अपनाने की अपेक्षा है।"

- अतः यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्यापार सूचना 25 अप्रैल, 2018 से पूर्व शुरू की गई जांचों के लिए लागू नहीं है। इस प्रकार, आवेदकों के लिए व्यापार सूचना में दिए गए प्रपत्र के अनुसार संशोधित आवेदन पत्र दायर करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, आवेदकों ने प्राधिकारी के पास सभी अपेक्षित सूचना दायर की है और वर्तमान जांच में निष्कर्ष निकालने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई भी सूचना देने के इच्छुक हैं।

"वाणिज्यिक मात्रा" शब्द नियम 22 तथा करार के अनुच्छेद 9.5 के अनुरूप नहीं है। मात्राओं से संबंधित नियम 22 और अनुच्छेद 9.5 में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, जहां कहीं करार मानदंड के रूप में मात्रा देते हैं, वहां विशेष रूप से इस प्रकार उल्लेख किया गया है:

- सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए, 5 प्रतिशत पर्याप्तता परीक्षण निर्धारित है।
- अर्थक्षमता परीक्षण के लिए 80-20 प्रतिशत परीक्षण निर्धारित है।
- न्यूनतम मात्रा के लिए, आयात मात्रा तक 3 प्रतिशत, 7 प्रतिशत निर्धारित है।

- न्यूनतम पाटन मार्जिन के लिए निर्यात कीमत का 2 प्रतिशत है।
- घरेलू उद्योग के आधार के लिए घरेलू उत्पादकों के उत्पादन का 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत अपेक्षित है।

नियमावली और करार के अनुसार ऐसे कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं। निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए कोई न्यूनतम मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। अतः "वाणिज्यिक मात्रा" के रूप में प्रयुक्त शब्द नियमावली और करार के अनुरूप नहीं है।

किसी भी स्थिति में, व्यापार सूचना जारी करने की तारीख अर्थात् 29 जनवरी, 2019 के बाद दायर किए गए सभी एनएसआर आवेदन पत्रों पर व्यापार सूचना लागू होगी। इस प्रकार, वह वर्तमान जांच पर लागू नहीं है।

- vi. आईजेएमए का यह दावा कि नियम 22 का अभिप्राय है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यातिकों को उनके अपने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन देने के लिए बाध्य नहीं है, पूर्णतः गलत और अनौचित्यपूर्ण है। नियम 22 में विशेष रूप से समीक्षाधीन उत्पादक/निर्यातिक के लिए अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण अपेक्षित है जो उसके सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर न कि किसी अन्य कंपनी के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है। न्यू शिपर समीक्षा के लिए नियम 17 का संदर्भ भी यह दर्शाता है कि "**जांच के तहत बस्तु के संबंधित प्रत्येक ज्ञात निर्यातिक अथवा उत्पादक के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेंगे**" (नियम 17 का पैरा 3)। न्यू शिपर समीक्षा नियम 22 से शासित होती है और नियम 22 में नमूनाकरण के लिए कोई संदर्भ नहीं है।
- vii. न्यू शिपर समीक्षा किसी एक से कम पाटन मार्जिन का दावा करने से उत्पादक/ निर्यातिक को नहीं रोकता जो कि मूल जांच में गैर नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक के लिए निकाला गया था।
- viii. आईजेएमए का यह दावा कि वही पाटन मार्जिन बांग्लादेश से गैर नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों के लिए निकाला गया है, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 और पाटनरोधी शुल्क के नियम 22 के अनुरूप नहीं है।
- ix. आईजेएमए द्वारा दिया गया यह तर्क उस स्थिति में जहां अलग पाटन मार्जिन उनके अपने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर आधारित है जिससे आईजेएमए द्वारा सुझाए गए पाटनरोधी शुल्क की तुलना में कम पाटन मार्जिन बनता है, समीक्षा दायर कर सकते हैं और विभिन्न प्रावधानों के तहत पाटनरोधी शुल्क की वापसी ले सकते हैं। यह विवरण विरोधाभासी है, यदि आईजेएमए नियम 22 के तहत न्यू शिपर के अधिकारों को नहीं मानता तो उसी न्यू शिपर को वापसी के प्रावधान के तहत अधिकार कैसे हो सकते हैं जब किसी न्यू शिपर समीक्षा जांच में उसके लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया है?
- x. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 9.5 में यह उल्लेख है कि पाटनरोधी शुल्क की पृथक दर प्राप्त करने के लिए न्यू शिपर को पात्र बनाने हेतु निर्यातों की न्यूनतम मात्रा के संबंध में कोई अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। भारत को निर्यात की कम मात्रा एनएसआर आवेदन पत्र को रद्द करने और इस आधार पर पाटन मार्जिन की पृथक प्रदान न करने के लिए कोई कारण नहीं हो सकता। निर्यात की मात्रा एनएसआर जांच में पृथक शुल्क प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त हो सकती है।
- xi. पाटनरोधी नियमावली का नियम 22 और वही ऐसा कोई मात्रात्मक प्रतिबंध निर्धारित नहीं करता, अतः आईजेएमए के दावे को नहीं समझ पा रहे हैं कि व्यक्तिगत निर्यातिक द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा इन निर्यातिकों की प्रश्नावली के उत्तर तथा उनका सामान्य मूल्य और उनकी निर्यात कीमत के आधार पर अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण मानदंड है। न तो पाटन मार्जिन करार और न नियमावली यह निर्धारित/उल्लिखित करती है कि कोई निर्यातिक प्रश्नावली का उत्तर दायर करने के लिए पात्र हो सकता है और अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए निर्यातों की विशिष्ट मात्रा दर्शनी की आवश्यकता है। किसी निर्यातिक द्वारा निर्यात की मात्रा अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए उसकी पात्रता हेतु मानदंड नहीं है।
- xii. विगत में डीजीटीआर ने कई न्यू शिपर समीक्षा जांचों में निष्कर्ष निकाला है जिनमें उन्होंने पाटनरोधी शुल्क (अलग पाटन मार्जिन) की अलग दर प्रदान की है। मैसर्स नेचुरल जूट मिल (उत्पादक/निर्यातिक), बांग्लादेश और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल एलएलसी (निर्यातिक/व्यापारी), संयुक्त राज्य अमेरिका एतद्वारा पिछले वर्षों में डीजीटीआर द्वारा निष्कर्ष निकाले गए कुछ न्यू शिपर समीक्षा जांचों की सूची दे रहे हैं:

| क्रम सं. | मामले का नाम | एनएसआर की शुरूआत | एनएसआर बंतिम जांच परिणाम |
|----------|---|------------------|--------------------------|
| 1 | पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के तहत मैसर्स तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लि., पाकिस्तान (निर्यातिक) के अनुरोध पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "क्लीयर फ्लोट ग्लास" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की न्यू शिपर समीक्षा | 23.09.2015 | 10.04.2017 |
| 2 | मैसर्स चांग चुन प्लास्टिक क. लि., चीनी तैपई के अनुरोध पर चीनी तैपई से "एसीटोन" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क पर सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के नियम 22 के तहत न्यू शिपर समीक्षा | 20.04.2011 | 17.04.2013 |
| 3 | चीन जन. गण. के मूल के/अथवा वहां से निर्यातित "नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक (एनटीसीएफ)" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की न्यू शिपर समीक्षा (नियम 22 के तहत) | 11.07.2006 | 08.04.2008 |
| 4 | मैसर्स युआसा बैट्री गुआंगडोंग कं. लि., चीन जन. गण. के अनुरोध पर "लेड एसिड बैट्रीज" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की न्यू शिपर समीक्षा | 27.08.2002 | 27.04.2004 |
| 5 | चीन जन. गण. के मूल के/अथवा वहां से निर्यातित "कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स (सीएफएल)" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की न्यू शिपर समीक्षा (नियम 22 के तहत) | 15.02.2005 | 12.11.2007 |
| 6 | कोरिया गणराज्य से "कैथोड रे कलर पिक्चर ट्यूब्स" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की न्यू शिपर समीक्षा (नियम 22 के तहत) | 13.11.2009 | 19.07.2010 |

अतः इससे यह स्पष्ट है कि डीजीटीआर ने न्यू शिपर समीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार किए हैं और न्यू शिपर समीक्षा जांचों की शुरूआत की है तथा पाटनरोधी शुल्क की अलग दरें प्रदान की हैं। इससे डीजीटीआर को विगत पूर्वोदाहरणों का पालन करना चाहिए और मैसर्स नेचुरल जूट मिल (उत्पादक/निर्यातिक), बांग्लादेश और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल एलएलसी (निर्यातिक/व्यापारी), संयुक्त राज्य अमेरिका को पाटनरोधी शुल्क की अलग दरें प्रदान करनी चाहिए।

- xiii. घेरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्क तर्कसंगत नहीं हैं और इस प्रकार सामान्य डीजीटीआर परिपाठी तथा पाटनरोधी कानूनों से अलग हैं। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसे स्वीकार करना पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 और पाटनरोधी करार के नियम 9.5 के उल्लंघन में होगा। माननीय महानिदेशक से अनुरोध है कि वे इसकी बारीकी से जांच करें।
- xiv. प्रत्युत्तर के माध्यम से यह अनुरोध है कि मैसर्स नेचुरल जूट मिल्स एक मालिकाना फर्म है जिसकी स्थापना जूट यार्न के उत्पादन की दृष्टि से मार्च, 2017 के पहले सप्ताह के दौरान की गई थी। जांच की अवधि के दौरान आवेदक ने घेरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है और क्रिएशन ग्लोबल एलएलसी, संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से भारत को निर्यात किया है।
- xv. क्रिएशन ग्लोबल एलएलसी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेट ऑफ मिशिगन में निर्मित एक सीमित देयता कंपनी है। यह जूट यार्न के उत्पादन में नहीं लगती है।
- xvi. व्यापार सूचना संख्या 01/2019 न्यू शिपर समीक्षा (एनएसआर) जांचों के लिए प्रक्रिया को सुकर बनाने हेतु 29 जनवरी, 2019 को जारी की गई थी जिसमें प्राधिकारी द्वारा "वाणिज्यिक मात्रा" की नई संकल्पना का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित रूप में पठित है:

"ग) एनएसआर आवेदन पत्र पर प्राधिकारी द्वारा तभी विचार किया जाएगा यदि एनएसआर आवेदन में आवेदन पत्र देने से पूर्व संबंधित उत्पाद के लिए "वाणिज्यिक मात्राओं" में भारत को वास्तविक निर्यात किया हो।"

"वाणिज्यिक मात्रा" शब्द नियम 22 तथा करार के अनुच्छेद 9.5 के अनुरूप नहीं है। मात्राओं से संबंधित नियम 22 और अनुच्छेद 9.5 में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, जहां कहीं करार मानदंड के रूप में मात्रा देते हैं, वहां विशेष रूप से इस प्रकार उल्लेख किया गया है:

- सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए, 5 प्रतिशत पर्यासता परीक्षण निर्धारित है।
- अर्थक्षमता परीक्षण के लिए 80-20 प्रतिशत परीक्षण निर्धारित है।
- न्यूनतम मात्रा के लिए, आयात मात्रा तक 3 प्रतिशत, 7 प्रतिशत निर्धारित है।
- न्यूनतम पाटन मार्जिन के लिए निर्यात कीमत का 2 प्रतिशत है।
- घरेलू उद्योग के आधार के लिए घरेलू उत्पादकों के उत्पादन का 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत अपेक्षित है।

नियमावली और करार के अनुसार ऐसे कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं। निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए कोई न्यूनतम मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। अतः "वाणिज्यिक मात्रा" के रूप में प्रयुक्त शब्द नियमावली और करार के अनुरूप नहीं है।

किसी भी स्थिति में, व्यापार सूचना जारी करने की तारीख अर्थात् 29 जनवरी, 2019 के बाद दायर किए गए सभी एनएसआर आवेदन पत्रों पर व्यापार सूचना लागू होगी। इस प्रकार, वह वर्तमान जांच पर लागू नहीं है।

xvii. आवेदक ने प्राधिकारी को पूर्ण आवेदन एवं उत्तर दायर किया है तथा एतद्वारा माननीय महानिदेशक से शुल्क की अलग दर प्रदान करने के लिए अनुरोध करते हैं।

उ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

- i. आवेदक उत्पादक/निर्यातक ने कोई टिप्पणी दायर नहीं की है।
- ii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि:
 - क. घरेलू उद्योग मानता है कि वर्तमान मामले में कोई कानूनी अथवा वास्तविक मुद्दा उठाना आवश्यक नहीं है। चूंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले ही माना है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी का पाटन मार्जिन निर्धारित करने का कोई इरादा नहीं है और इसीलिए घरेलू उद्योग द्वारा कोई अनुरोध अनावश्यक हो जाता है।
 - ख. यदि कोई अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करना आवश्यक मानता है तो प्राधिकारी को दूसरा प्रकटन विवरण जारी करना अपेक्षित होता है, यदि निर्धारण वर्तमान प्रकटन विवरण की तुलना में प्रतिकूल होना प्रस्तावित हो।
 - ग. सेस्टेट ने एच एंड आर जानसन (इंडिया) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में निम्नलिखित माना। "शो" शब्द आवेदक द्वारा केवल यह मानने की औपचारिकता निर्धारित करने के लिए नहीं है कि आवेदक "संबद्ध" नहीं है बल्कि पहले यह जांच करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को सावधान कर प्रवंचनारोधी उपाय नियम 22 में शामिल करने के लिए है कि क्या संभावित रूप से प्रवंचनाकारी संबंध विद्यमान है।
 - घ. उपर्युक्त सेस्टेट के निर्णय में यह माना गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का दुरुपयोग रोकने के लिए प्राधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि नियम 22 का दुरुपयोग नहीं हो रहा है।
 - ड. वर्तमान मामले में आवेदकों ने ऐसा कुछ नहीं दिया है जिसका यह अर्थ निकल सके कि आवेदकों ने प्राधिकारी को यह दर्शाया है कि वे नियम 22 की अपेक्षा पूरी करते हैं। आवेदक यह साक्ष्य देने में विफल रहे हैं कि वे उस निर्यातक देश में किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबद्ध नहीं हैं जो उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन हो, यदि उसे सिद्ध करने के लिए साक्ष्यों को एक तरफ छोड़ दे। कानून के तहत अपेक्षा "दर्शाना", अर्थात् "प्रदर्शित करना" है न कि "दावा" अथवा "उल्लेख" करना है।
 - च. एन एस आर जांच में यह दर्शाए जाने की आवश्यकता है कि एक न्यू शिपर समीक्षा मामले में जांच की अवधि के दौरान न्यू शिपर आवेदक द्वारा किए गए निर्यात अधिकृत वाणिज्यिक लेन देन है, जो पाटन मार्जिन के लिए

आधार होता है। उद्देश्य “व्यापार का उचित मूल्य सुनिश्चित करना नहीं था बल्कि उसके वाणिज्यिक उपयुक्ता के लिए प्रत्येक बिक्री की जांच करना था” ।

छ. यह सिद्ध है कि निर्यातक ने पहले न्यूशिपर समीक्षा की मांग कर और अब असहयोगी बनकर प्राधिकारी के समक्ष पूरी कार्यवाही को कृत्रिम बनाया है।

ज. इसके अतिरिक्त यह तथ्य कि संभावित जांच की अवधि के पूरा एक वर्ष होने के बावजूद केवल तीन लेनदेन किए गए हैं, यह दर्शाता है कि आवेदक निर्यातक भारतीय बाजार के संबंध में गंभीर नहीं है। प्राधिकारी ने निम्नलिखित सही-सही नोट किया है :

प्राधिकारी का आवेदक उत्पादक/निर्यातक को अलग पाटन मार्जिन प्रदान करने का विचार नहीं है क्योंकि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों उपर्युक्त सीमाओं/कमियों के मद्देनजर विश्वसनीय रूप से सिद्ध नहीं किए जा सकते।

च. प्राधिकारी द्वारा जांच

11. पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में निम्नलिखित प्रावधान है :

“22. ऐसे निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन जिनकी मूल रूप से जांच नहीं की गई थी

(1) यदि किसी उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित नियातिक देश के किसी भी नियातिक अथवा उत्पादक, जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को उस उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवधिक समीक्षा करेंगे, बशर्ते ये नियातिक अथवा उत्पादक यह सिद्ध करते हैं कि वे नियातिक देश के किसी नियातिक अथवा उत्पादक से सम्बद्ध नहीं हैं, जिन पर उस उत्पाद हेतु पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।

(2) केन्द्रीय सरकार इस नियम के उप नियम (1) में यथा संदर्भित नियातिकों अथवा उत्पादकों से किए गए आयातों पर जांच अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण नहीं करेगी।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार अनंतिम आकलन करे और यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी संस्तुति करते हों तो आयातक से गारंटी प्राप्त करे और यदि ऐसी समीक्षा की परिणति ऐसे उत्पादों अथवा नियातिकों के संबंध में पाटन के निर्धारण में होती हो, तो ऐसे मामलों में वह समीक्षा की शुरूआत की तारीख से, भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क अधिरोपित करेगी।”

12. विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:-

“9.5 यदि कोई उत्पाद आयातक सदस्य में पाटनरोधी शुल्क के अधीन हो तो प्राधिकारी जांच के अधीन नियातिक देश में ऐसे किसी नियातिक या उत्पादक के लिए पाटन के अलग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ तत्काल समीक्षा करेंगे जिसने जांच अवधि के दौरान आयातक सदस्य को उत्पाद का निर्यात नहीं किया हो बशर्ते कि ये नियातिक या उत्पादक यह दर्शा सकता हो कि वे नियातिक देश में ऐसे किसी नियातिक या उत्पादक से संबंधित नहीं हैं जो उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं। ऐसी कोई समीक्षा आयातक सदस्य में सामान्य शुल्क निर्धारण और समीक्षा कार्यवाही की तुलना में सक्रिय आधार पर शुरू की जाएगी और चलाई जाएगी। समीक्षा के दौरान ऐसे नियातिकों या उत्पादकों से आयातों पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाएगा। तथापि, प्राधिकारी मूल्यांकन को रोक सकते और/या यह सुनिश्चित करने के लिए गारंटी का अनुरोध कर सकते हैं कि यदि ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप ऐसे उत्पादकों या नियातिकों के संबंध में पाटन का निर्धारण होता है तो पाटनरोधी शुल्क को समीक्षा की शुरूआत की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाया जा सके।”

13. उपर्युक्त नियमावली, डब्ल्यूटीओ करार में प्रावधानों और डीजीटीआर की विगत परिपाटी के अनुसार न्यू शिपर समीक्षा जांच पाटनरोधी शुल्क लगाने वाले संबद्ध देश से किसी भी नियातिक अथवा उत्पादक के संबंध में अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों के तहत की जानी होती है:

- i. यह कि नियातिक अथवा उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात न किया हो।

- ii. यह कि निर्यातक अथवा उत्पादक यह दर्शाएं कि वे उस निर्यातक देश में किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबद्ध नहीं हैं जो संबंधित उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन हों।
14. वर्तमान मामले में मैसर्स नेचुरल जूट मिल (उत्पादक/निर्यातक), बांगलादेश और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल एलएलसी (निर्यातक/व्यापारी), संयुक्त राज्य अमेरिका ने जूट यार्न पर अलग पाटन मार्जिन की मांग करते हुए प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है और न्यू शिपर समीक्षा की शुरूआत के लिए अनुरोध किया है।
15. जहां तक "एनएसआर" का दावा करने के लिए उत्पादक/निर्यातक की पात्रता का संबंध है, प्राधिकारी ने मूल जांच में उत्पादक/निर्यातक द्वारा दायर आंकड़ों/सूचना के संबंध में उत्पादक/निर्यातक द्वारा किए गए दावों का सह-संबंध बनाया है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य द्वारा एनएसआर के लिए उत्पादक/निर्यातक द्वारा शर्त पूरी न करने का कोई साक्ष्य नहीं दिया है। अतः प्राधिकारी ने उत्पादक/निर्यातक को न्यू शिपर समीक्षा के लिए पात्र माना है।

आवेदक के लिए अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक उत्पादक/निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को दो असंबद्ध व्यापारियों अर्थात मैसर्स सिनोचेन हेबेई कारपोरेशन (** मी. टन), और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल एलएलसी (** मी. टन) के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद अर्थात जूट यार्न के केवल *** मी. टन का निर्यात किया है। यद्यपि मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल एलएलसी ने तदनुरूपी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं, तथापि मैसर्स सिनोचेन हेबेई कारपोरेशन द्वारा कोई उत्तर दायर नहीं किया गया है। अतः उत्पादक/निर्यातक ने कुल *** मी. टन निर्यात में से केवल *** मी. टन के लिए पूर्ण उत्तर दायर किया है। निर्यात की इस *** मी. टन मात्रा में जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के कुल निर्यातों का एक प्रतिशत भी नहीं है जो कि आवेदक उत्पादक/निर्यातक को अलग पाटन मार्जिन प्रदान करने के लिए अपनाए जाने हेतु वाणिज्यिक रूप से प्रतिनिधि कारक मात्रा के रूप में माने जाने के लिए बहुत ही अपर्याप्त है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने उल्लेख किया है कि किसी न्यू शिपर समीक्षा जांच में निर्यात किए जाने के लिए न्यूनतम मात्रा के संबंध में कोई निर्धारण नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान प्रतिनिधि कारक होने के लिए निर्यात कीमत स्थापित करने हेतु जांच की अवधि के दौरान न्यू शिपर द्वारा किए जाने वाले निर्यातों की मात्रा के संबंध में कोई निर्धारण नहीं है, निर्यातों की मात्रा और उनका विस्तार ऐसा होना चाहिए कि निर्यात कीमत प्रतिनिधि कारक, उपयुक्त और विश्वसनीय सिद्ध की जा सके। इस मामले में, यद्यपि वर्तमान जांच की अवधि का पहला वर्ष दिया गया था जिससे न्यू शिपर उत्पादक/निर्यातक वांड के तहत निर्यात करने के लिए सक्षम बन गया, केवल तीन माल निर्यात किए गए थे। इनमें से एक लेन-देन के लिए उपर्युक्त निर्यातक द्वारा कोई उत्तर दायर नहीं किया गया है। *** मी. टन के दो निर्यात लेन-देनों को प्रतिनिधिकारक के रूप में निर्यात कीमत सिद्ध करने का औचित्य नहीं बनाया जा सकता।
17. जहां तक सामान्य मूल्य के दावे का संबंध है, आवेदक उत्पादक/निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद के *** मी. टन की विक्री सूचित की है। यद्यपि जांच की अवधि के दौरान सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू विक्री प्रतिनिधिकारक है, तथापि जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादक/निर्यातक द्वारा दायर किए गए लागत संबंधी आंकड़ों की निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में वैधता अपेक्षित है:
- जांच की अवधि के लिए लेखापरीक्षित लेखे
 - प्रैक्टिस करने वाले लेखाकार द्वारा लागत फॉर्मेट का प्रमाणन
 - क्रय रजिस्टर जो आदि और अंत स्टॉक तथा नमूना बिलों के साक्ष्यों सहित कच्ची सामग्री की खपत के साक्ष्य दे
 - उत्पादन और विक्री (माह-वार), मूल्यहास के ब्यौरे तथा वित्त लागत संबंधी स्पष्टीकरण
18. उत्पादक/निर्यातक ने डीजीटीआर से दिनांक 22.03.2019 और 01.04.2019 के अनुरोधों के बावजूद अनुरोध किए गए आंकड़े और सूचना नहीं दी। ऐसी स्थिति में घरेलू विक्री का सत्यापन व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता। अतः प्राधिकारी ने आवेदक उत्पादक/निर्यातक को कोई अलग पाटन मार्जिन प्रदान नहीं किया है क्योंकि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत उपर्युक्त सीमाओं/कमियों के मद्देनजर विश्वसनीय रूप से सिद्ध नहीं की जा सकती।

छ. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

19. अतः प्राधिकारी मानते हैं कि दी गई परिस्थितियों में और मामले के तथ्यों के तहत उत्पादक/निर्यातक को पाटनरोधी शुल्क की कोई अलग दर प्रदान नहीं की जा सकती। दिनांक 03.04.2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 11/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) में शुल्क तालिका की क्रम संख्या 20 और 23 के तहत शेष श्रेणी के तहत आवेदक उत्पादक/निर्यातक पर लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की जाती है।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
Department of Commerce
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2019

FINAL FINDINGS

Subject: New Shipper Review under Rule 22 of Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 pertaining to Anti-Dumping Duty imposed on the imports of Jute Products" viz – Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian Fabric and Jute Yarn originating in or exported from Bangladesh, as requested by M/s Natural Jute Mill (Producer/Exporter), Bangladesh and M/s Kreation Global LLC (exporter/trader), USA regarding Jute Yarn initiated on 18.01.2018.

F. No. 7/09/2017-DGAD: Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. Whereas, in the original Anti-Dumping investigation, the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) recommended, inter alia, imposition of anti-dumping duty on the imports of "Jute products" viz- Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabric, and Jute sacking bags, originating in or exported from Bangladesh and Nepal, falling under Chapter 69 of the Customs Tariff Act, 1975, vide Final findings Notification No. 14/19/2015-DGAD dated 20th October, 2016. The Central Government notified the definitive anti-dumping duty vide Notification No. 01/2017-Customs (ADD) -Customs dated 5th January 2017 and Customs Notification No. 11/2017-Cus (ADD) dated 3rd April, 2017.
3. M/s Natural Jute Mill (Producer/Exporter), Bangladesh and M/s Kreation Global LLC (Exporter/Trader), USA filed an application for New Shipper Review (NSR) in terms of Rule 22 of the Anti-dumping Rules read with the Customs Tariff Act, requesting for a New Shipper Review (NSR) claiming individual dumping margin in respect of imports of the Jute Yarn originating in or exported from Bangladesh which was not exported by them during the POI of the original investigation wherein AD measure has been imposed vide Custom Notification no. 11/2017-Cus (ADD) dated 3rd April, 2017.
4. The Authority, having been *prima facie* satisfied with the conditions laid down under Rule 22 of Anti-dumping Rules, initiated a New Shipper Review investigation, vide Notification No. 7/9/2017-DGAD dated 18th January 2018, for determination of individual dumping margin for the purposes of imposition of the anti-dumping duties levied on the dumped imports of Jute Yarn (subject goods) originating in or exported from Bangladesh, in respect of M/s Natural Jute Mill (Producer/Exporter), Bangladesh and M/s Kreation Global LLC (Exporter/Trader), USA. .
5. Ministry of Finance notified the provisional assessment on exports made by of M/s Natural Jute Mill (Producer/Exporter), Bangladesh and M/s Kreation Global LLC (Exporter/Trader), USA Limited for the subject goods till completion of the aforesaid NSR investigation vide Notification No. 16/2018-Customs (ADD) dated 23rd March, 2018.
6. The period of investigation for the purpose of this New Shipper Review was fixed as 1st January, 2018 to 31st December, 2018.

B. PROCEDURE

7. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation:
 - (i) The Authority issued a public notice vide Notification No. 7/09/2017-DGAD dated 18th January 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject NSR anti-dumping investigation.
 - (ii) The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the applicant along with a copy of the exporter's questionnaire and gave them opportunity to make their views known in writing, and filing relevant data in the prescribed Questionnaire, after expiry of the POI.
 - (iii) The Authority also forwarded a copy of the initiation notification to the High Commission of Bangladesh in India.
 - (iv) The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the known domestic producers in India and gave them opportunity to make their views known in writing.
 - (v) In response to the initiation notification, Questionnaire response was filed, the applicant M/s Natural Jute Mill (Producer/Exporter), Bangladesh and M/s Kreation Global LLC (Exporter/Trader), USA for NSR.
 - (vi) The Authority made available non-confidential version of submissions/ information filed by various interested parties, in the form of a public file, kept open for inspection by interested parties.
 - (vii) The Authority held an Oral Hearing on 14th February, 2019 to provide an opportunity to interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6) followed by written submissions. The interested parties were allowed to present rebuttal rejoinders on the views/information presented by other interested parties. The Authority has considered submissions received from various interested parties appropriately.
 - (viii) The Authority issued a disclosure statement dated 22nd April 2019 to the Participating Interested Parties.
 - (ix) All relevant Submissions/comments made by interested parties, during the course of this investigation have been considered and included in this disclosure statement.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

8. The product under consideration in the original investigation is 'Jute Products' comprising of Jute yarn/twine (multiple folded/cabled and single), Hessian Fabrics and Jute Sacking bags. The Authority had recommended separate duty for each type of Jute products in the original investigation to producers. This investigation is pertaining to exports of Jute Yarn only i.e. one of the product types of the PUC considered in original investigation, as stated in the Para 1 of the initiation notification dated 18.1.2018.

D. SUBMISSIONS BY VARIOUS INTERESTED PARTIES AND DOMESTIC INDUSTRY :

9. Submissions by the Domestic Industry:

- i. The investigation was initiated on 18th Jan., 2018. The Authority had formulated new questionnaire format for NSR investigation even before the initiating the case on 25th April, 2018. The petition may have been filed before the issuance of the trade notice, nevertheless the applicant had an obligation to file updated information as per the trade notice after initiation. Despite having sufficient time and knowledge, the applicant did not revise information as per the new application proforma.
- ii. While a bonafide new shipper has the right to seek individual margins, but at the same time the Designated Authority needs to ascertain that the claims are bonafide and there is no abuse/ misuse/ circumvention of anti-dumping duties. It is for this reason that the applicant needs to be strictly put to establish that (a) they are genuine/bonafide exporters who have made bonafide sales (b) they have not exported goods in the original investigation and (c) they are not related to producer or exporter of subject goods who is attracting anti-dumping. The exporters have not fulfilled these criteria
- iii. The exporter or producer should show that they have not exported the subject goods during the period of investigation of original investigation and that they are not related producers who have exported goods in the original POI. There is nothing in the application and subsequent submissions which shows that this requirement is fulfilled with the support of evidences.
- iv. The applicant sought prospective period as period of investigation i.e., a period which is subsequent period to the initiation of investigation under Rule 22. The concept of prospective POR has been heavily criticized by the CESTAT in *Tiles* case
- v. By the reason of prospective period of investigation, the applicants have been able to manipulate and doctor the price by (a) making only ceremonial exports, i.e., 45MT of exports, (b) at artificially high price. It is pertinent to note here that despite imposition of ant dumping duties, imports from Bangladesh was around 45000 MT during the POI against which the exports made by the applicant is merely 45MT which is 0.1% of exports!!

- vi. During the oral hearing the applicant had argued that low exports were because the provisional assessment notification by the central government came on 23rd March 2018. Within 2 months of initiation the Central Government issued notification for provisional assessment of goods. The Applicant still had 9 months to exports goods but still chose to export only 45MT goods.
- vii. Once the investigation got initiated the applicant could have easily enters into contract with potential customers to exports their goods. Thus, the applicant has not made proper use of time period it had after the notification was issued as can be seen from the exports made by it during this 9 month period. It has only made two exports throughout the POI, which indicates that they are not serious about the present investigation
- viii. It seems from the conduct of the applicant that they are not serious about the fate of the present matter and the current exercise is to try their luck if they can get a favourable margin, as can be seen from the fact that they have exported only twice after filing the application and procuring a prospective POI. The applicant has also secured a trader for its product in USA and not India and China where it has made exports
- ix. The Authority has in past, initiated new shipper review investigations only upon satisfaction of sales made or firm commitment made for exports. The exports made by the applicants during the period of investigation in a new shipper review case must be a bona fide commercial transaction to be a basis for a dumping margin. It needs to be seen whether the sales under consideration is typical and will be representative of the new shipper's future sales. If a producer's or exporter's transactions involve price, quantities, and overall circumstances that do call into question the commercial viability of those sales, the genuineness of those sales, both in terms of value and volume, should be examined
- x. Other country laws, such as US, Brazil, Canada, EU, Turkey, Taiwan and Vietnam etc are pertinent to note in this regard, which also provides that the transactions undertaken by the exporter should be bonafide and commercial in nature
- xi. The Authority has specifically prescribed that the quantities exported by the exporter should be in commercial quantity so as to receive an individual margin of dumping. The applicant had argued that the trade notice was issued recently and thus will have effect for future cases, it is submitted that the principle highlighted is not a new principle. The principle of actual exports been made in commercial quantity has been recognized by the Authority as well as Hon'ble CESTAT in past. Thus the principle is very much applicable to the present Reference is made to Hon'ble CESTAT order in H and R Johnson (India) Limited Vs. Designated Authority and Authority's past judgement in PCV Flex Film, R-134 a, Jute Products by Janata Jute Mills etc.
- xii. There is no questionnaire response from the importers of the product under consideration. This further smoke conscious attempt to suppress the fact that a token export was made at unrealistic price in order to obtain a low or no dumping margin and thereafter aggressively dump the volumes
- xiii. The applicants have claimed excessive confidentiality without any good cause and for the sole objective of hiding information from the domestic industry and preventing the domestic industry from defending its interests.
- xiv. Without prejudice to the above submission that the applicant has not established its case for grant of individual dumping margin, if the Authority concludes that applicant satisfies the condition and individual duties are justified, it is then submitted that the applicant may be given the weighted average duties given to the cooperating companies not included in the sample in the original investigation, since the original investigation involved sampling.
- xv. The Domestic Industry also submits in rejoinder as regards argument of the applicant that the use of term 'commercial quantities' is not in consonance with Indian Rules and WTO Ant-dumping Agreement, the domestic industry would like to reiterate its stance that the term commercial quantities is not incompatible with WTO and Indian ADD Rules, the requirement for exporters seeking a new shipper review is prevalent not only in various WTO member countries domestic laws, this requirement has also been discussed in Indian jurisprudence, most notably in HR Johnson case.
- xvi. If an exporter is allowed a margin based only on a small volume of exports or based on an expectation of exports, this would open the scope for manipulation of prices by the exporter for obtaining a lower margin. It is for this very reason that most jurisdictions have introduced a further condition of significant exports or commercial export transactions or commitment to export significant exports as an eligibility criterion for exporters seeking a new shipper review.
- xvii. Antidumping law in each WTO contracting countries is based on the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, i.e., the parent agreement. Thus the laws in these countries are in consonance with the parent agreement and all the legal provisions formulated by these countries

and practise followed is subject to the WTO scrutiny. Thus the practise of other countries provides a fair guidance to the principles involved and methodologies that may be followed in the anti-dumping investigation.

10. Submissions by the Applicant Exporter:

- i. It is submitted that the applicants have provided all the information as and when sought by the Authority. The petitioners satisfy the requirements of Rule 22 and the same has already been examined by the Authority then only present investigation was initiated. The claims of the IJMA are baseless and vague.
- ii. The applicants hereby submit that they have filed the application for initiation of NSR investigation with the Authority on 22nd May 2017 as per Rule 22 for determination of individual dumping margin of anti-dumping duty imposed on dumped imports. Thereafter a deficiency letter was issued by the Authority dated 17th July 2017. The applicants have provided all the information vide letter dated 28th August 2017. The applicants have also filed supplementary information vide letter dated 26th December 2018 in response to a letter No. 7/9/2017-DGAD dated 7th December 2017 issued by the Hon'ble Designated Authority. Then the Authority, after examining all the information provided by the applicants, initiated the present investigation on 18th January 2018. The petitioners have also filed the required questionnaire responses as per new format with the Authority vide letter dated 11th February 2019. Thus, all the information available with the petitioners is provided to the Authority.
- iii. It is also submitted that IJMA is raising fingers at the wisdom of the Authority to initiate this investigation. This aspect has been examined in detail by the Authority before the initiation of the present investigation and this is not the right time to raise such baseless issues.
- iv. The trade notice, which IJMA is talking about was issued on 25th April 2018 stating that:
“4. All interested parties are required to follow the enclosed application format for filing any new request for initiation of New Shipper Review after the date of issuance of this notice”
- v. So, it is clear that the said trade notice is not applicable for the investigations initiated before 25th April 2018. Thus, the applicants are not required to file the revised application as per proforma provided in the trade notice. However, the applicants have filed all the requisite information with the Authority and are further willing to provide any information as required by the Authority to conclude the present investigation.

The word “commercial quantities” is not in consonance with the Rule 22 and Article 9.5 of the agreement. There is nothing provided in Rule 22 and Article 9.5 related to quantities, wherever, the agreement gives the quantity as criteria, it has specifically mentioned such as:

- For Calculation of Normal Value, 5% sufficiency test is prescribed.
- For Viability Test, 80-20% test is prescribed.
- For De-minimus qty, 3%,7% of the Import Volume is prescribed.
- For De-minimus dumping margin, 2% of the EP is prescribed.
- For Standing of the domestic industry, 25%, 50% of production of the domestic producers is required.

As per the Rules and the Agreement, there are no such guidelines. For determination of Export Price, no minimum quantity has been prescribed. Therefore, the word used as “Commercial Quantities” is not in line with the Rules and Agreement.

In any event, the Trade Notice shall be applicable to all NSR applications filed after the date of issue of the Trade Notice i.e. 29th January 2019. Thus, the same is not applicable on the present investigation.

- vi. The claim of IJMA that Rule 22 implies that the Designated Authority is not obliged to give dumping margin to the exporters on the basis of their own normal value and export price, is totally incorrect and unjustified. Rule 22 specifically required determination of individual dumping margin for the producer/exporter under review which can be determined only based on his Normal Value and Export Price and not based on some other entities’ Normal Value and Export Price. Reference to Rule 17 for a New Shipper Review also shows that the *“Designated Authority shall determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the article under investigation”* (para 3 of Rule 17). New shipper review is governed by Rule 22 and there is no reference to sampling in Rule 22.
- vii. New shipper review does not bar a producer/exporter from claiming a lower dumping margin than the one which was worked out for non-sampled cooperating producers in the original investigation.
- viii. Claim of IJMA that the same dumping margin as has been worked out for non-sampled cooperating exporters from Bangladesh is not in conformity with Article 9.5 of Anti-Dumping Agreement and Rule 22 of Anti-Dumping Rules.

- ix. The arguments raised by IJMA that in a situation where the individual dumping margin based on their own normal and export price, leading to lower dumping margin as compared to the anti-dumping duty suggested by IJMA can file a review and refund of anti-dumping duty under different provisions. This statement is self-contradictory. In case, IJMA does not recognize the rights of a new shipper under Rule 22, how can the same new shipper have rights under the refund provision when no separate dumping margin is determined for him in a new shipper review investigation?
- x. Article 9.5 of the WTO Agreement states that there is no mandatory requirement about minimum volume of exports to make a New Shipper eligible to get separate rate of anti-dumping duty. The low volume of export to India cannot be a reason for rejecting an NSR Application and not granting separate rate of dumping margin on this ground, volume of export can be a necessary condition to get a separate of duty in an NSR investigation.
- xi. Rule 22 of Anti-dumping Rules and the same does not prescribe any such volume restrictions. Hence, we are unable to understand the claim of the IJMA that volume of exports made by individual exporter is important parameter for determining individual dumping margin on the basis of questionnaire response of these exporters and their normal value and export price. Neither Anti-Dumping Agreement nor Rules prescribe/specify that an exporter can be eligible for filing questionnaire response and determination of individual dumping margin needs to show a specified volume of exports. Volume of exports by an exporter is not a criterion for its eligibility for determination of individual dumping margin.
- xii. In past, DGTR has concluded number of new shipper review investigations whereby, they have granted individual rate of anti-dumping duty (individual Dumping Margin). M/s Natural Jute Mill, Bangladesh and M/s Kreation Global LLC, USA, are hereby listing some of the New Shipper Review investigations concluded by DGTR in the past years:

| S. No. | Case Name | NSR Initiation | NSR Final Finding |
|--------|--|----------------|-------------------|
| 1 | New Shipper Review of anti-dumping duty imposed on the imports of “Clear Float Glass” originating in or exported from Pakistan, Saudi Arabia and UAE requested by M/s. Tariq Glass Industries Ltd., Pakistan (exporter) under Rule 22 of the Anti-Dumping | 23.09.2015 | 10.04.2017 |
| 2 | New Shipper Review under Rule 22 of Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 on the Anti-Dumping duty imposed on imports of “Acetone” from Chinese Taipei, as requested by M/s. Chang Chun Plastic Co., Ltd., Chinese Taipei | 20.04.2011 | 17.04.2013 |
| 3 | New Shipper Review (under Rule 22) of Antidumping duty imposed on imports of “Nylon Tyre Cord Fabric (NTCF)” originating in/or exported from China PR | 11.07.2006 | 08.04.2008 |
| 4 | New Shipper Review of Anti-Dumping duty imposed on imports of “Lead Acid Batteries” requested by M/s. Yuasa Battery Guangdong Co. Ltd. China PR | 27.08.2002 | 27.04.2004 |
| 5 | New Shipper Review (under Rule 22) of Anti-dumping duty imposed on imports of “Compact Fluorescent Lamps (CFL)” originating in/or exported from China PR | 15.02.2005 | 12.11.2007 |
| 6 | New Shipper Review (under Rule 22) of Antidumping duty imposed on imports of “Cathode ray Color Picture Tubes” from Korea RP | 13.11.2009 | 19.07.2010 |

So, from it is clear that DGTR has accepted new shipper review applications and initiated the new-shipper review investigations and granted individual rates of anti-dumping duty. Thereby, DGTR should follow the past precedents and grant individual rates of anti-dumping duty to M/s Natural Jute Mill (Producer/Exporter), Bangladesh and M/s Kreation Global LLC (Exporter/Trader), USA.

- xiii. Arguments raised by the domestic industry are illogical and thus deviate from the normal DGTR practice and Anti-Dumping Laws. The same cannot be accepted and acceptance of the same will be in violation of Rule 22 of Anti-Dumping Rules and Rule 9.5 of Anti-Dumping Agreement. The Hon'ble Director General is requested to critically examine the same.

- xiv. It is submitted by way of rejoinder that M/s Natural Jute Mills is a proprietorship firm which was established during the first week of March 2017 with a view to produce Jute Yarn. During the period of investigation, the applicant has sold PUC in the domestic market and exported to India through Kreation Global LLC, USA.
- xv. Kreation Global LLC is limited liability company formed in State of Michigan in USA. It is not engaged in production of the Jute Yarn.
- xvi. The Trade Notice 01/2019 was issued on 29th January 2019 for streamlining the procedure for New Shipper Review (NSR) investigations wherein a new concept of “commercial quantities” is used by the Authority, read as under:

“c) The NSR application shall be entertained by the Authority only if the NSR applicant has undertaken actual exports to India in “commercial quantities” for the product concerned before making the application.

The use of word “commercial quantities” is not in consonance with the Rule 22 and Article 9.5 of the Agreement. There is nothing provided in Rule 22 and Article 9.5 related to quantities, wherever, the agreement gives the quantity as criteria, it has specifically mentioned such as:

- For Calculation of Normal Value, 5% sufficiency Test is prescribed.
- For Viability Test, 80-20% test is prescribed.
- For De-minimus qty, 3%,7% of the Import Volume is prescribed.
- For De-minimus dumping margin, 2% of the EP is prescribed.
- For Standing of the Domestic Industry 25%, 50% production of the domestic producers is required.

As per Rules and Agreement, there is no such guidelines. For determination of Export Price, no minimum quantity has been prescribed. Thus, the word used as “Commercial Quantities” is not in line with the Rules and Agreement.

In any event the Trade Notice shall be applicable to all NSR applications filed after the date of issue of the Trade Notice i.e. 29th January 2019. Thus, the same is not applicable on the present investigation.

- xvii. The applicant has filed complete application and response with the Authority and hereby requests the Hon'ble Director General to grant individual rate of duty

E. POST DISCLOSURE COMMENTS

- i. The applicant producer/exporter has not filed any comments.
- ii. The Domestic Industry has submitted that:-
 - a. The domestic industry considers that it is not necessary to raise any legal or factual issues in the present case. Since the Designated Authority has already held that the Designated Authority does not intend to determine dumping margin, and therefore any submissions by the domestic industry becomes unnecessary.
 - b. In case a considers necessary to determine individual dumping margin, the Authority is required to issue another disclosure statement, if the determination is proposed to be reversed as compared to the present disclosure statement
 - c. CESTAT in the matter of H & R Johnson (India) Limited Vs. Designated Authority held as follows:
The word “show” is not meant to prescribe just a formality of a bare assertion by the applicant that the applicant is not “related” but is meant to incorporate in Rule 22 an anti-circumvention measure by alerting the designated authority to examine first whether potentially circumventing relationship exists.
 - d. The above CESTAT decision has held that in order to prevent misuse of the imposition of anti dumping duty, the authority should ensure that the Rule 22 is not being misused.
 - e. In the present case, the applicants have provided nothing which can be construed to imply that the applicants have shown to the Designated Authority that they satisfied the requirement under Rule 22. The applicants have failed to provide evidence that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product, leave aside the evidences to establish the same. The requirement under the law is “to show”, i.e., “demonstrate” and not “claim” or “state”.
 - f. In NSR investigation, it needs to be shown that exports made by the new shipper applicant during the period of investigation in a new shipper review case is bona fide commercial transaction, which is to be the

basis for a dumping margin. The purpose was not to “ascertain the fair value of the merchandise, but examine each sale for its commercial reasonableness”.

- g. It is evident that the exporter has mocked the entire proceedings before by the Authority by first seeking new shipper review and now becoming non-cooperative.
- h. Further the fact that only three transactions have been undertaken despite having one complete year of prospective POI shows that the applicant exporter is not serious about the Indian market. The Authority has rightfully noted as follows:

The Authority therefore does not propose to accord individual Dumping Margin to the applicant Producer/Exporter since both Normal Value and export price cannot be credibly established in view of the aforesaid limitations/deficiencies.

F. EXAMINATION BY AUTHORITY

11. Rule 22 of the Anti-Dumping Rules provides as follows –

“22. Margin of dumping, for exporters not originally investigated.

(1) If a product is subject to anti-dumping duties, the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product.

(2) The Central Government shall not levy anti-dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule:

Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee from the importer if the designated authority so recommends and if such a review results in a determination of dumping in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of the initiation of the review.”

12. Article 9.5 of the WTO Agreement states as under –

“9.5 If a product is subject to anti-dumping duties in an importing Member, the authorities shall promptly carry out a review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to the importing Member during the period of investigation, provided that these exporters or producers can show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product. Such a review shall be initiated and carried out on an accelerated basis, compared to normal duty assessment and review proceedings in the importing Member. No anti-dumping duties shall be levied on imports from such exporters or producers while the review is being carried out. The authorities may, however, withhold appraisement and/or request guarantees to ensure that, should such a review result in a determination of dumping in respect of such producers or exporters, anti-dumping duties can be levied retroactively to the date of the initiation of the review.”

13. In terms of the aforesaid Rule, provisions in the WTO Agreement and the past practice of DGTR, a New Shipper Review investigation is to be carried out under following circumstances for the purpose of determining individual dumping margin in respect of any exporter or producer from the subject country attracting ADD:

- i. that the exporter or producer has not exported the product under consideration during the period of investigation, and
 - ii. that exporter or producer shows that they are not related to any of the exporter or producer in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product concerned.
14. In the instant case M/s Natural Jute Mill (Producer/Exporter), Bangladesh and M/s Kreation Global LLC (Exporter/Trader), USA has filed an application before the Authority seeking individual dumping margin on jute yarn and requested for initiating the new shipper review.
 15. As regards the eligibility of the producer/exporter for claiming ‘NSR’, the Authority has correlated the claim made by the producer/exporter with respect to data/ information filed by the producer/exporter in the original investigations. No interested party has provided evidence of non-fulfilment of condition by the

producer/exporter for NSR by way of any substantive evidence. The Authority therefore considered the producer/exporter to be eligible for a New Shipper Review.

Determination of individual Dumping Margin for the applicant

16. The Authority notes that the applicant Producer/Exporter has exported only *** MT of Product Under Consideration i.e Jute Yarn during Period of Investigation to India, through two unrelated traders i.e M/s Sinochem Hebei Corporation (***) MT and M/s Kreation Global LLC. (***) MT. While M/s Kreation Global LLC has filed corresponding Exporters Questionnaire Response, no response has been filed by M/s Sinochem Hebei Corporation Though The Producer/Exporter has therefore filed complete response only for *** MT out of the total of the total exports of *** MT. This export Quantity of *** MT constitutes not even 1% of the total exports of Product Under Consideration to India during Period of Investigation, which is too insignificant to be considered as Commercially representative Quantity to be adopted for according individual Dumping Margin to the applicant Producer/Exporter. The Authority notes that the producer/exporter has stated that there is no stipulation on minimum quantity to be exported in an New Shipper Review investigation. The Authority notes that even though there is no stipulation on the quantum of exports to be made by a New Shipper during the POI, to establish the export price to be representative during POI, the quantum and spread of exports should be such that the export price can be established as representative, appropriate and reliable. In the instant case though one year of prospective POI was provided which enabled the New Shipper producer/exporter to export under bond, only three consignments were exported. For one of these transactions, no response has been filed by the associated exporter. The two export transactions amounting to *** MT can not justify establishment of the export price as representative.
17. As regards claim of Normal Value, the applicant Producer/ Exporter has reported sales of *** MT of Product Under Consideration in the domestic market during Period of Investigation. The domestic sales is though representative for Normal Value determination during POI, the cost data filed by Producer/Exporter for Product Under Consideration during the Period of Investigation required validation on the following aspects:
 - Audited Accounts for POI
 - Certification of costing formats by practicing accountant
 - Purchase register evidencing opening/closing stock and raw material consumption with evidence of sample bills
 - Details of production and sales (month wise), depreciation and clarification on finance cost
18. The producer/exporter despite requests from DGTR dated 22/3/2019 and 1/4/2019 did not provide the requested data and information. In event of this, the domestic sales cannot be verified to be in the ordinary course of trade. The Authority therefore has not accorded any individual Dumping Margin to the applicant Producer/Exporter since both Normal Value and export price cannot be credibly established in view of the aforesaid limitations/deficiencies.

G. Conclusions and Recommendations

19. The Authority therefore holds that under the given circumstances and facts of the case, the producer/exporter can not be accorded any individual rate of ADD. The existing ADD on the applicant producer/exporter levied under the residual category under S.Nos. 20 and 23 of the duty table in Customs Notification No. 11/2017-Customs (ADD) dated 3/4/2017 is recommended to be continued.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. and Director General